माननीय ए.एल. बाहरी और एन.के. कपूर ज.के समक्ष।

ज्ञान चंद वालिया,-याचिकाकर्ता।

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य,-प्रतिवादी।

सी.डब्ल्यू.पी. 1993 का 5259

17 जनवरी 1994

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद, 14, 226/227-हरियाणा नगरपालिका कर्मचारी पेंशन और सामान्य भविष्य निधि नियम, 1993- विधेयक 2(1)-हरियाणा नगरपालिका संशोधन अधिनियम 1992 में संशोधन किए जाने की तारीख से पेंशन योजना के कार्यान्वयन के लिए अंतिम तिथि निर्धारित करना-ताकि नगरपालिका समितियों को पेंशन के लिए धन उपलब्ध कराने और व्यय करने की अनुमति मिल सके- अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं है!

माना गया कि इस प्रकार अप्रैल 1992 में एक तारीख तय करना जो कि पूर्वोक्त संशोधन के अनुरूप था, बिल्कुल भी मनमानी या काल्पनिक तारीख नहीं है। नगरपालिका समितियों के कर्मचारियों को पेंशन लाभ की अनुमति देने के लिए कोई भी तारीख तय करने का अधिकार राज्य के पास था। निर्धारित तिथि से पहले सेवानिवृत्त हुए नगर पालिका के ऐसे कर्मचारियों को

अंशदायी निधि योजना का लाभ मिला। ऐसे कर्मचारी जो अप्रैल, 1992 से ठीक पहले सेवा में थे, उन्हें अंशदायी निधि योजना द्वारा शासित बने रहने या पेंशन योजना द्वारा शासित होने का विकल्प दिया गया था।

(पैरा 9)

याचिकाकर्ता के वकील आर. पी. सिंह अहलूवालिया।

अरुण नेहरा, अतिरिक्त ए.जी. हरियाणा, संजीव शर्मा, प्रतिवादी के वकील।

निर्णय

ए एल बहरी, जे.

(1) ज्वार यह देखें; orderaacbunchVoft रिटयाचिकाएंW(C.W3P. Nos.)। 5343, 5344, 5345, 5346, 6091, 6092. 6093, 6094, 6095, 6096, 6097, 6098, 6099. 6100, 9829, 13060 एवं 15218 ऑफ 1993) का निस्तारण किया जा रहा है। मुख्य निर्णय सी.डब्लू.पी. 1993 का क्रमांक 5259 में तैयार किया गया है।

(2) राज्य नगरपालिका समिति के पुनर्गठन के बाद भी हरियाणा पंजाब के प्रावधानों द्वारा शासित होता रहा हरियाणा में लागू नगरपालिका अधिनियम के अनुसार, ऐसी नगरपालिका

समितियों के कर्मचारी राज्य कर्मचारी नहीं थे, इसलिए एक नगरपालिका समिति से दूसरी समिति में उनके स्थानांतरण पर विचार नहीं किया गया था। ये सभी नगर पालिकाओं के कर्मचारी थे। हरियाणा नगरपालिका समिति अधिनियम, आईडी i6 (बाद में अधिनियम जे कहा जाता है) को हरियाणा राज्य में लागू किया गया था जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों की नगरपालिका समितियों को प्रांतीयकृत किया गया था। तब से सभी कर्मचारी पेंशन योजना लागू करने की मांग उठा रहे थे, यह देखा जा सकता है नगरपालिका समितियों के कर्मचारी पहले अंशदायी भविष्य निधि योजनाओं द्वारा शासित होते थे। अंततः हरियाणा राज्य ने इस संबंध में नगरपालिका समितियों के कर्मचारियों की मांग को स्वीकार कर लिया। हरियाणा नगरपालिका संशोधन अधिनियम, 1992 (हरियाणा अधिनियम संख्या 14) 1992) (संक्षेप में '1992 का अधिनियम' कहा जाता है) पारित किया गया जिसे 8 अप्रैल, 1992 को हरियाणा के राज्यपाल की सहमति प्राप्त हुई। इस अधिनियम की अधिसूचना 16 अप्रैल, 1992 को हरियाणा सरकार के राजपत्र (अतिरिक्त) में प्रकाशित हुई थी। हरियाणा नगरपालिका अधिनियम की धारा 38 और 57 में संशोधन किए गए, जिसमें हरियाणा राज्य में नगरपालिका समिति को पेंशन के लिए भी धन उपलब्ध कराने के लिए अधिकृत किया गया। उप-धारा (1) के खंड (एम) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 257 को हरियाणा नगरपालिका अधिनियम की

धारा 38 और 39 के साथ पढ़ा जाता है, हरियाणा सरकार ने 5 मार्च 1993 को अधिसूचना जारी की (अनुलग्नक पीएल) नियम तैयार किए जिन्हें हरियाणा नगरपालिका कर्मचारी पेंशन और सामान्य भविष्य निधि नियम, 1993 कहा जाता है (इसके बाद 'नियम कहा जाएगा) '). ऐसे नियम 16 अप्रैल, 1992 से लागू हुए। नियमों के नियम 2 में प्रावधान है:-

नियम: "2(1) ये नियम नगर पालिकाओं के उन कर्मचारियों पर लागू होंगे जो: -

(i) 16 अप्रैल 1992 के दिन या उसके बाद पूर्णकालिक नियमित आधार पर नियुक्त किए गए थे/हैं; और

(ii) 16 अप्रैल, 1992 से ठीक पहले काम कर रहे थे और इन नियमों का विकल्प चुनते हैं"

(3) याचिकाकर्ताओं ने 16 अप्रैल, 1992 से पहले विभिन्न नगरपालिका समितियों की सभी रिट याचिकाएं सेवानिवृत्त कर दीं और इस प्रकार वे इन पेंशन नियमों के लाभ के हकदार नहीं थे। उन्होंने रिट याचिकाओं के इस सेट में इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है और दावा किया है कि राज्य सरकार ने मनमाने ढंग से पेंशन नियमों को लागू करने की तारीख 16 अप्रैल, 1992 तय की, जिसके परिणामस्वरूप सेवानिवृत्त लोगों के बीच भेदभाव पैदा हुआ। जो याचिकाकर्ता पूर्व में सेवानिवृत्त हो चुके थे! वे पहले से आहरित अंशदायी भविष्य निधि को सरेंडर करने के इच्छुक थे और कुछ याचिकाकर्ता ऐसे भी हैं जिन्होंने इसे वापस नहीं लिया है। वे उपरोक्त पेंशन

नियमों के लाभ का दावा करते हैं। उन्होंने इस संबंध में अभ्यावेदन भी दिया जिसका कोई नतीजा नहीं निकला।

(4) प्रस्ताव का नोटिस जारी होने पर उत्तरदाताओं ने अन्य बातों के साथ-साथ लिखित बयान दायर करके रिट याचिका का विरोध किया है, जिसमें कहा गया है कि पेंशन योजना के कार्यान्वयन के लिए कट-ऑफ तारीख 16 अप्रैल, 1992 तय की गई थी क्योंकि यह उस तारीख से प्रभावी थी। हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 में संशोधन करके नगरपालिका समितियों को पेंशन के लिए धन उपलब्ध कराने और उन्हें उस खाते पर व्यय करने की अनुमति दी गई। उन्होंने 1973 की सिविल अपील संख्या 3472 (पश्चिम बंगाल राज्य बनाम रतन बिहारी देव और अन्य) के समर्थन में 6 अगस्त, 1993 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी भरोसा किया। हमने पक्षों के विद्वान वकील को सुना है। लंबाई और हमारा विचार है कि याचिकाकर्ताओं के पक्ष में कोई मामला नहीं बनता है।

(5) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने **डी.एस. नकारा और अन्य बनाम भारत संघ**[1]**,** में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए तर्क दिया है कि पेंशन नियमों में तय की गई तारीख 16

---

[1]**(1983) 2 एस.सी.आर. 165**

अप्रैल, 1992 का अनुदान के मामले में कोई संबंध नहीं है। पेंशन का 1992 में नियम लागू होने के बाद से, इससे पहले के सभी सेवानिवृत्त लोग समान स्तर पर खड़े होंगे। जब राज्य ने 16 अप्रैल, 1992 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए सेवानिवृत्त लोगों को लाभ देने का निर्णय लिया, तो उससे पहले सेवानिवृत्त हुए लोगों को पेंशन नियमों का लाभ देने से इनकार करने का कोई कारण नहीं था। उच्चतम न्यायालय ने **डी.एस. नाकारा के मामले (सुप्रा**) में निम्नानुसार टिप्पणी की है: -

"सामाजिक-आर्थिक न्याय के व्यय क्षितिज के साथ, सोशलिस्ट रिपब्लिक एंड वेलफेयर स्टेट जिसे हम स्थापित करने का प्रयास करते हैं और काफी हद तक इस तथ्य से प्रभावित है कि बूढ़े लोग जो वृद्ध व्यक्ति वेतन के समय सेवानिवृत्त हुए थे, वे तुलनात्मक रूप से कम थे और लगातार बढ़ती कीमतों की अनिश्चितताओं के संपर्क में थे, जिसके परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति वाले निवेशों के रूप में रनियों का मूल्य गिर रहा था, हम संतुष्ट हैं कि एक मनमाना पात्रता मानदंड पेश करके: 'सेवा में रहना और निर्दिष्ट तिथि के बाद सेवानिवृत्त होना' उदारीकृत पेंशन योजना के पात्र होने के लिए और इस प्रकार एक सजातीय वर्ग को विभाजित करना, वर्गीकरण किसी स्पष्ट तर्कसंगत सिद्धांत पर आधारित नहीं है और उदारीकृत पेंशन के अनुदान द्वारा प्राप्त की जाने वाली उद्देश्यों से पूरी तरह से असंबंधित पाए जाने और तैयार किए गए पात्रता

मानदंड पूरी तरह से मनमाने ढंग से होने के कारण हमारा विचार है कि उदारीकृत पेंशन योजना के लिए 'निर्दिष्ट तिथि पर सेवा में रहने और उस तिथि के बाद सेवानिवृत्त होने' की पात्रता विवादित ज्ञापनों में है। पी. एल. और पी. 2 अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हैं और असंवैधानिक हैं और निरस्त किए जाते हैं।दोनों ज्ञापनों को लागू और कार्यान्वित किया जाएगा जैसा कि नीचे पढ़ा गया हैः

(6) दूसरे शब्दों में, Ex। पी. एल., शब्दः

'उन सरकारी सेवकों के संबंध में जो 31 मार्च, 1979 को सेवा में थे और उस तारीख को या उसके बाद सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे थे'। पी.2, शब्द: 'पेंशन की नई दरें 1 अप्रैल, 1979 से प्रभावी हैं और उन सभी सेवा अधिकारियों पर लागू होंगी जो उस तारीख को या उसके बाद अप्रभावी हो गए/बन गएःये असंवैधानिक हैं और इस विनिर्देश के साथ रद्द कर दिए गए हैं कि उसमें उल्लिखित तारीख उस तारीख के रूप में प्रासंगिक होगी जिससे उदारीकृत पेंशन योजना 1972 के नियमों द्वारा शासित सभी पेंशनभोगियों के लिए लागू हो जाती है, चाहे सेवानिवृत्ति की तारीख कुछ भी हो। असंवैधानिक भाग को हटाते हुए यह घोषित किया जाता है कि 1972 के नियमों और सेना पेंशन विनियमों द्वारा शासित सभी पेंशनभोगी निर्दिष्ट तिथि से पेंशन योजना के हकदार होंगे,

चाहे सेवानिवृत्ति की तारीख कुछ भी हो।नई गणना के अनुसार निर्दिष्ट तिथि से पहले पेंशन का अवशिष्ट स्वीकार्य नहीं है।"

याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील की दलील स्वीकार नहीं की जा सकती। डी. एस. नकारा के मामले में निर्णय को उस विषय पर सर्वोच्च न्यायालय के बाद के निर्णयों में समझाया गया था जिसका संदर्भ दिया जा सकता है। **कृष्ण कुमार बनाम भारत संघ और अन्य**[2]**,** में, सुप्रीम कोर्ट उन रेलवे कर्मचारियों को पेंशन देने के मामले से निपट रहा था जो पहले भविष्य निधि योजना द्वारा शासित थे। पेंशन योजना पर स्विच करने के लिए एक कट-ऑफ तारीख तय की गई थी और यह तर्क उठाया गया था कि अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होने के कारण यह बुरा है। पैरा 30 में नकारा के मामले (सुप्रा) का संदर्भ देने के बाद, इसे निम्नानुसार देखा गया: - "इस प्रकार न्यायालय ने पेंशन सेवानिवृत्त लोगों को केवल एक सजातीय वर्ग के रूप में माना। आर.एफ. सेवानिवृत्त लोगों का ध्यान नहीं था। 'न्यायालय ने यह भी स्पष्ट रूप से देखा कि इसे पढ़ते समय, यह किसी भी मामले में लेन-देन नहीं कर रहा था और उसी केक को निर्दिष्ट तिथि के संबंध में अधिसूचना के तहत बड़ी संख्या में पेंशनभोगियों के बीच विभाजित करने का कोई सवाल ही नहीं था।1972 के नियमों द्वारा शासित सभी पेंशनभोगियों को एक वर्ग के रूप में

[2]**1990 (2) आरएसजे 434**

माना जाता था क्योंकि प्रत्येक पेंशनभोगी की मृत्यु तक भुगतान या पेंशन राज्य की ओर से एक सतत दायित्व था और अंशदायी भविष्य निधि के मामले के विपरीत, पेंशन के उदारीकरण में एक निधि का कोई सवाल ही नहीं था।"

फैसले के पैरा 32 में, इसे इस प्रकार देखा गया: - "नाकारा में यह कभी नहीं माना गया कि पेंशन सेवानिवृत्त और पी.एफ. दोनों सेवानिवृत्त लोगों ने एक समरूप वर्ग का गठन किया और उनके बीच कोई भी आगे वर्गीकरण अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। दूसरी ओर न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह "फंड" की समस्या से नहीं निपट रहा था। रेलवे अंशदायी भविष्य निधि परिभाषा के अनुसार एक निधि है, इसके अलावा, सी.पी.एफ. के तहत एक कर्मचारी के प्रति सरकार का दायित्व है। समतुल्य योगदान देने की योजना उसका खाता खुलते ही शुरू हो जाती है और उसकी सेवानिवृत्ति के साथ समाप्त हो जाती है जब भविष्य निधि के संबंध में सरकार के पास उसके अधिकार अंततः स्पष्ट हो जाते हैं और उसके बाद कोई वैधानिक दायित्व जारी नहीं रहता है। क्या अब भी कोई नैतिक दायित्व बाकी है, यह अलग बात है।"

(7) इसके बाद इस मामले पर **अखिल भारतीय रिजर्व बैंक सेवानिवृत्त अधिकारी संघ और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य[3],** मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फिर से विचार किया गया।

---

[3]**जेटी 1991 (6) एससी 400**

1 जनवरी, 1986 से प्रभावी होने के लिए 31 अक्टूबर, 1990 को तैयार की गई पेंशन योजना को शुरू करते समय डी. एस. नकारा और कृष्ण कुमार मामले में पहले के फैसले का उल्लेख किया गया था, जिसे वैध माना गया था। कट-ऑफ तिथि तय करने से संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं हुआ। निम्नलिखित, टिप्पणियों पर ध्यान दिया जा सकता है: -

"अंतर्निहित सिद्धांत यह है कि जब राज्य पेंशनभोगियों को दिए गए सामाजिक सुरक्षा कवर को बढ़ाने की दृष्टि से मौजूदा पेंशन योजना को संशोधित और उदार बनाने का निर्णय लेता है, तो वह आमतौर पर पेंशनभोगियों के एक वर्ग को लाभ नहीं दे सकता है और दूसरों को इससे वंचित नहीं कर सकता है। एक कृत्रिम कट-ऑफ रेखा खींचना जिसे तर्कसंगत आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता है और जो लक्ष्य हासिल किया जाना है, उससे पूरी तरह से असंबद्ध है। लेकिन जब एक नियोक्ता एक पूरी तरह से नई योजना पेश करता है जिसका मौजूदा योजना से कोई संबंध नहीं होता है, तो निर्णय लेने की प्रक्रिया में विभिन्न विचार शामिल होते हैं। ऐसा एक विचार योजना के वित्तीय निहितार्थ और नियोक्ता की बोझ वहन करने की क्षमता की सीमा हो सकता है। योजना के कारण पड़ने वाले वित्तीय बोझ को वहन करने की अपनी क्षमता को ध्यान में रखते हुए, नियोक्ता को योजना की प्रयोज्यता की सीमा पर निर्णय लेना होगा। यही कारण है कि नाकारा के मामले में इस न्यायालय ने मौजूदा योजना को उसके उदारीकृत रूप में जारी

रखने और एक पूरी तरह से नई योजना की शुरूआत के बीच अंतर किया; पूर्व के मामले में सभी पेंशनभोगियों को समान आधार पर पेंशन का अधिकार था और कोई भी विभाजन जो उन्हें कट-ऑफ तारीख पेश करके दो आधारों में वर्गीकृत करता है, आमतौर पर उपचार में समानता के सिद्धांत का उल्लंघन होगा जब तक कि इसके लिए कोई मजबूत तर्क न हो। ऐसा करने पर इस आधार पर इसका समर्थन किया जा सकता है कि यह उस उद्देश्य को पूरा करेगा जिसे प्राप्त करना चाहा गया है। लेकिन एक नई योजना के मामले में, जहां सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पास कोई निहित अधिकार नहीं है, नियोक्ता इसे सेवानिवृत्त लोगों के कुछ वर्ग तक ही सीमित नहीं कर सकता है, तथ्य-स्थिति को ध्यान में रखते हुए जिसमें इसे पेश किया गया था, सीमा इससे जो अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा, उसे वहन करने की नियोक्ता की क्षमता, उनकी सेवानिवृत्ति की तारीखों की परवाह किए बिना सभी सेवानिवृत्त लोगों के लिए योजना का विस्तार करने की व्यवहार्यता, प्रत्येक सेवानिवृत्त व्यक्ति के रिकॉर्ड की उपलब्धता, आदि।

(8) यही सिद्धांत हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा रतन बिहारी देव के मामले में भी निर्धारित किया गया था, जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है। 1982 में कर्मचारियों की मांग प्राप्त होने पर अंशदायी निधि योजना, कट-ऑफ तिथि अप्रैल, 1977 को प्रतिस्थापित करने के लिए पेंशन योजना को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया। यह माना गया कि कट-ऑफ

तारीख मनमाने ढंग से तय नहीं की गई थी। उपरोक्त उल्लिखित डी. एस. नकारा और कृष्ण कुमार मामलों का संदर्भ दिया गया था।

(9) उपरोक्त उल्लिखित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों में निर्धारित सिद्धांत को वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू करते हुए, यह मानने की कोई गुंजाइश नहीं है कि कट-ऑफ तिथि मनमाने ढंग से तय की गई थी।

राज्य द्वारा तय किया गया. 16 अप्रैल, 1952 को हरियाणा नगरपालिका संशोधन अधिनियम, 1992 को सरकार की मंजूरी 8 अप्रैल, 1992 को मिली और इसे हरियाणा राजपत्र में प्रकाशित किया गया। हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 38 और 57 में पेश किए गए संशोधनों के माध्यम से पेंशन निधि और उस पर व्यय के लिए प्रावधान किए गए थे। इस प्रकार अप्रैल, 1992 में एक तारीख तय करना जो कि उपरोक्त संशोधन के अनुरूप था, बिल्कुल भी मनमानी या काल्पनिक तारीख नहीं है। नगरपालिका समितियों के कर्मचारियों को पेंशन लाभ की अनुमति देने के लिए कोई भी तारीख तय करने का अधिकार राज्य के पास था। निर्धारित तिथि से पहले सेवानिवृत्त हुए नगर पालिका के ऐसे कर्मचारियों को अंशदायी निधि योजना का लाभ मिला। ऐसे कर्मचारी जो अप्रैल 1992 से ठीक पहले सेवा में थे, उन्हें अंशदायी निधि योजना द्वारा शासित बने रहने या पेंशन योजना द्वारा शासित होने का विकल्प दिया गया था। इसी

संदर्भ में नगरपालिका अधिनियम की धारा 38 और 57 में संशोधन करते समय 'भविष्य निधि' शब्द नहीं हटाया गया। यह विचार किया गया कि कुछ कर्मचारी भविष्य निधि योजना द्वारा शासित होने का विकल्प चुन सकते हैं। केवल 'पेंशन' शब्द पेश किया गया था क्योंकि हरियाणा नगरपालिका अधिनियम में संशोधन करते समय विधानमंडल द्वारा सैद्धांतिक रूप से निर्णय लिया गया था कि कर्मचारियों को पेंशन का लाभ दिया जाएगा, पेंशन नियम बनाने में ऐसे प्रावधान किए गए थे, जो संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करते हैं।

रिट याचिकाओं में कोई योग्यता नहीं पाते हुए, उन्हें खारिज कर दिया जाता है। कोई लागत नहीं.

जे.एस.टी.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए हैताकि वह अपनी भाषा में इसेसमझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

सिद्धार्थ कपूर

प्रशिक्षु न्यायिक पदाधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

फरीदाबाद, हरियाणा